राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 3421/2024

सपना निमावत पत्नी श्री हेमेन्द्र निमावत, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी 179, गली नं. 2, ओड़ बस्ती, अम्बामाता, जिला उदयपुर.---- याचिकाकर्ता

बनाम

2. रविज शर्मा पुत्र अज्ञात, निवासी एसआई, पीएस अम्बामाता, उदयपुर.---- प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री तुषार मोद.

प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री एच.एस. जोधा, पीपी

श्री कैलाश खत्री - आर/2.

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

10/09/2024

1. भारतीय दंड संहिता की धारा 448, 427 और 143 के अंतर्गत कथित अपराधों के लिए पुलिस स्टेशन अंबामाता, जिला उदयपुर में दिनांक

14.05.2024 को दर्ज एफआईआर संख्या 217/2024 को रद्द करने और सभी परिणामी कार्यवाही की मांग की जाती है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि पुलिस अधीक्षक, उदयपुर को एक पुलिस शिकायत मिली थी जिसमें कहा गया था कि कुछ व्यक्ति महाकालेश्वर महादेव जी सिद्ध धाम मंदिर में अराजकता पैदा कर रहे थे। शिकायत की जांच के दौरान, प्रतिवादी संख्या 2 - शिकायतकर्ता ने गवाहों के बयान दर्ज किए और एक वीडियो सीडी प्राप्त की। वीडियो की समीक्षा करने पर, यह पाया गया कि याचिकाकर्ता ने अन्य लोगों के साथ मिलकर दरवाजे पर लगे ताले को काटकर जबरन मंदिर में प्रवेश करने का प्रयास किया। परिणामस्वरूप, प्रतिवादी संख्या 2 ने उचित कार्रवाई के लिए थाना अंबामाता, उदयपुर के एसएचओ को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके परिणामस्वरूप संबंधित एफआईआर दर्ज की गई।

3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील, मंदिर ट्रस्ट के विद्वान वकील (जो पक्षकार नहीं हैं, लेकिन सुनवाई में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं) और विद्वान लोक अभियोजक को सुना है।

4. मामले का मूल यह है कि मंदिर के ट्रस्टियों ने दावा किया है कि उन्होंने श्रद्धालुओं को एक निश्चित बिंदु से आगे जाने से रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए हैं। हालांकि, आरोपियों ने कथित तौर पर जबरन बैरिकेड्स पार करने की कोशिश की, जिसके कारण एफआईआर दर्ज की गई। दिलचस्प बात यह है कि हालांकि ट्रस्ट शिकायतकर्ता प्रतीत होता है, लेकिन उसने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई। इसके बजाय, एफआईआर सब-इंस्पेक्टर राजीव शर्मा द्वारा दर्ज कराई गई, जिन्होंने दावा किया है कि उन्होंने घटना देखी है।

5. सबसे पहले, भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 427 के साथ 448 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है, आसान संदर्भ के लिए, प्रासंगिक धारा 141, 143, 427, 442 और 448 को निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया जाता है:

> 141. गैरकानूनी सभा.-- पांच या अधिक व्यक्तियों की सभा को "गैरकानूनी सभा" कहा जाता है, यदि उस सभा में शामिल व्यक्तियों का सामान्य उद्देश्य है
>
> पहला.- आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन से केंद्र या किसी राज्य सरकार या संसद या किसी राज्य के विधानमंडल या किसी लोक सेवक को ऐसे लोक सेवक की वैध शक्ति के प्रयोग में भयभीत करना; या
>
> दूसरा.- किसी कानून या किसी कानूनी प्रक्रिया के निष्पादन का विरोध करना; या
>
> तीसरा.- कोई शरारत या आपराधिक अतिचार या अन्य अपराध करना; या
>
> चौथा.- आपराधिक बल के माध्यम से किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति पर कब्जा करने या उस पर अधिकार प्राप्त करने के लिए बल प्रयोग करना या आपराधिक बल का प्रदर्शन करना, या किसी व्यक्ति को रास्ते के अधिकार या पानी के उपयोग या अन्य अमूर्त अधिकार से वंचित करना, जिसका वह कब्जा या उपयोग कर रहा है, या किसी अधिकार या कथित अधिकार को लागू करना; या आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन के माध्यम से किसी व्यक्ति को ऐसा करने के लिए मजबूर करना जिसे करने के लिए वह कानूनी रूप से बाध्य नहीं है, या ऐसा करने से चूकना जिसे करने का वह कानूनी रूप से हकदार

है। स्पष्टीकरण- कोई सभा जो एकत्रित होने के समय गैरकानूनी नहीं थी, बाद में गैरकानूनी सभा बन सकती है।

143. सजा- जो कोई भी गैरकानूनी सभा का सदस्य है, उसे छह महीने तक की अवधि के लिए कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। 427. पचास रुपए की राशि तक की क्षति पहुंचाने वाली शरारत।-

जो कोई शरारत करेगा और उसके द्वारा पचास रुपए या उससे अधिक की राशि की हानि या क्षति पहुंचाएगा, उसे दो वर्ष तक की अवधि के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।

442. गृह-अतिचार।--जो कोई किसी भवन, तम्बू या जलयान में प्रवेश करके या उसमें रहकर आपराधिक अतिचार करता है, जिसका उपयोग मानव निवास के रूप में किया जाता है या किसी भवन का उपयोग पूजा के लिए या संपत्ति की अभिरक्षा के लिए किया जाता है, उसे गृह-अतिचार करने वाला कहा जाता है।

स्पष्टीकरण।-आपराधिक अतिचारी के शरीर के किसी अंग का प्रवेश गृह-अतिचार के लिए पर्याप्त है।

448. गृह-अतिचार के लिए दंड।--जो कोई गृह-अतिचार करता है, उसे एक वर्ष तक की अवधि के कारावास या एक हजार रुपए तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।

6. उपरोक्त धाराओं को सरलता से पढ़ने पर पता चलता है कि एफआईआर में लगाए गए आरोप याचिकाकर्ता की ओर से किसी भी आपराधिक इरादे (मेन्स रीआ) को स्थापित नहीं करते हैं। आईपीसी की धारा 448 (घर में अनधिकार प्रवेश), 427 (नुकसान पहुँचाने वाली शरारत) और 143 (अवैध रूप से एकत्र

होना) के लिए आपराधिक इरादे या जानबूझकर अवज्ञा के तत्व की आवश्यकता होती है। इस मामले में, माना जाता है कि याचिकाकर्ता का मुख्य उद्देश्य पूजा स्थल, सार्वजनिक मंदिर तक पहुँचना था, जो अपने आप में एक वैध कार्य है। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि याचिकाकर्ता का इरादा नुकसान पहुँचाने, संपत्ति को नुकसान पहुँचाने या सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने का था। इसलिए, इन दंडात्मक प्रावधानों को लागू करने के लिए कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है।

7. मंदिर पूजा का एक सार्वजनिक स्थान है, जो जाति, पंथ या सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना सभी नागरिकों के लिए सुलभ है। निजी ट्रस्टियों द्वारा बैरिकेड्स या ताले लगाकर ऐसी जगह तक पहुँच को प्रतिबंधित करना प्रत्येक व्यक्ति के अपने धर्म का पालन करने और उसका प्रचार करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत गारंटी दी गई है। ट्रस्टी, मंदिर के मामलों का प्रबंधन करते समय, इस तरह से कार्य नहीं कर सकते हैं जो समाज के किसी या कुछ वर्ग, विशेष रूप से हाशिए पर पड़े लोगों को उनके पूजा करने के अधिकार से वंचित करता हो। इस प्रकार एफआईआर कानूनी प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग प्रतीत होता है, जिसे गुप्त उद्देश्यों से शुरू किया गया है। तथ्य यह है कि ट्रस्ट ने खुद शिकायत दर्ज नहीं की और एफआईआर एक सब-इंस्पेक्टर द्वारा दर्ज की गई, जिसने मुखबिर होने का दावा किया, शिकायत की विश्वसनीयता और वास्तविकता पर सवाल उठाता है।

8. याचिकाकर्ता की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पृष्ठभूमि को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, खासकर इस तथ्य के मद्देनजर कि ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए धार्मिक संस्थानों तक पहुंच प्रतिबंधित रही है। याचिकाकर्ता को प्रवेश से वंचित करना और उसके बाद की आपराधिक शिकायत जाति-आधारित भेदभाव का उदाहरण हो सकती

है। ट्रस्टियों द्वारा इस तरह का भेदभावपूर्ण आचरण न केवल समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, बल्कि सामाजिक बहिष्कार को भी बढ़ावा देता है, जो सभी नागरिकों, विशेष रूप से उत्पीड़ित समुदायों के लोगों के लिए सम्मान सुनिश्चित करने के संवैधानिक जनादेश के विपरीत है।

9. इसके अलावा, वीडियो साक्ष्य और तस्वीरें, जो एफआईआर का आधार बनती हैं, बलपूर्वक प्रवेश या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपों का समर्थन नहीं करती हैं। अधिक से अधिक, ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने सार्वजनिक मंदिर में प्रवेश करने के लिए बैरिकेड पार करने का प्रयास किया। हिंसा, बल या शरारत के किसी भी सबूत के बिना इस कृत्य को धारा 448 और 427 के तहत आपराधिक अतिचार या शरारत के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। संपत्ति को शारीरिक नुकसान या नुकसान के सबूत की अनुपस्थिति याचिकाकर्ता के खिलाफ मामले को और कमजोर करती है।

10. धारा 143 (अवैध सभा) का प्रयोग भी अनुचित है। अवैध सभा के लिए, ऐसे लोगों के समूह का होना आवश्यक है जिनका उद्देश्य कोई अवैध कार्य करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना हो। जैसा कि उल्लेख किया गया है, आरोप के अनुसार याचिकाकर्ता केवल मंदिर में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा था, जो कि कोई अवैध कार्य नहीं है। किसी भी हिंसक इरादे या सार्वजनिक अशांति के अभाव में, अवैध सभा का आरोप सही नहीं है।

11. संक्षेप में, पुनरावृत्ति की कीमत पर, ट्रस्ट/ट्रस्टियों को यह समझना चाहिए कि मंदिर एक सार्वजनिक स्थान है। केवल इसलिए कि यह कुछ ट्रस्टियों द्वारा प्रबंधित है, यह उनकी निजी संपत्ति नहीं है। प्रत्येक नागरिक को मंदिर में प्रवेश करने और प्रार्थना करने का अधिकार है। इस मामले में, ऐसा लगता है कि ट्रस्टी जनता के प्रवेश के अधिकार में अनावश्यक बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से

संबंधित है, इस कारण ट्रस्टियों में कुछ असहजता पैदा हो सकती है, जिसके कारण उन्हें प्रवेश से वंचित किया गया। ट्रस्टियों द्वारा इस तरह का आचरण अस्वीकार्य है।

12. मैं यहां यह जोड़ना चाहूंगा कि सुनवाई के दौरान ट्रस्ट के विद्वान वकील (हालांकि ट्रस्ट पक्षकार नहीं है) ने इस दावे के समर्थन में कुछ तस्वीरें पेश कीं कि याचिकाकर्ता और अन्य ने बैरिकेड्स तोड़ने के लिए बल का प्रयोग किया। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, तस्वीरों को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि महिलाओं में से एक (जिसे अदालत में मौजूद किसी भी व्यक्ति ने नहीं पहचाना) केवल बैरिकेड्स को पार करने का प्रयास कर रही थी, और उन्हें तोड़ने के लिए बल का प्रयोग करने का कोई संकेत नहीं है।

13. परिणामस्वरूप, याचिका को अनुमति दी जाती है। पुलिस स्टेशन अंबामाता, जिला उदयपुर में दिनांक 14.05.2024 को दर्ज एफआईआर संख्या 217/2024, भारतीय दंड संहिता की धारा 448, 427 और 143 के अंतर्गत कथित अपराधों के लिए, सभी परिणामी कार्यवाहियों सहित, निरस्त की जाती है।

14. लंबित आवेदन(ओं), यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।